एक नजर में

बिजली गिरने से तीन बच्चों की मौत

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का दौर जारी है. इंदौर और उज्जैन में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई. उज्जैन में सड़कों पर डेढ़ फीट तक पानी भर गया, तो भोपाल में भी दोपहर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई. धार में आकाशीय बिजली गिरने से तीन बच्चों की मौत हो गई. मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. उधर शाजापुर के कालापीपल और आसपास के ऊपरी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. इससे नदी-नालों में बाढ़ आ गई. 2 नालों के बीच एक स्कूल बस फंस गई थी. कालापीपल-अरनिया कला रोड पर आवागमन बंद होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है. नर्मदापुरम में भी शाम को तेज बारिश हुई. मौसम विभाग ने नीमच और रतलाम में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.

अंतर्विभागीय राज्य स्तरीय समिति का गठन

भोपाल, 16 जुलाई. राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के अधिसूचित इको सेंसेटिव जोन्स का जोनल मास्टर प्लान मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड बना रही है. उक्त जोन मास्टर प्लान के गजट नोटिफिकेशन से पूर्व परीक्षण एवं स्पष्ट अनुशंसा के लिये अंतर्विभागीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, वन विभाग होंगे. समिति में सदस्यों में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग और समिति के सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग होंगे. समिति के सदस्य सचिव अन्य सभी संबंधित विभागों से समान्वय स्थापित कर प्रति सप्ताह कार्य में हो रही प्रगति की स्थिति से अवगत करायेंगे.

अधूरी जानकारी देने पर रुकेगा वेतन

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश विधानसभा में अधूरे जवाब को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आयुक्त को नोटशीट लिखी है. इसमें लिखा है कि 2024 के विधानसभा सत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर अपूर्ण दिए गए है. अपूर्ण प्रश्नों की पूर्ण जानकारी 30 जुलाई तक भेजें. सचिव ने कहा कि ऐसे शाखा प्रमुख/ प्रभारी जिनके द्वारा अधूरे प्रश्नों के जवाब पूरी तरह नहीं भेजे जाते है, उनका जुलाई माह का वेतन आहरण रोक दिया जाएं. बता दें विधानसभा में अधूरे जवाब को लेकर विधायक कई बार आपत्ति दर्ज करा चुके है. अब नगरीय प्रशासन विभाग सचिव ने अधूरे जवाब भेजने वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है.

कांग्रेस और सारंग समर्थक आमने- सामने

टीआई को ज्ञापन देते कांग्रेसी

सारंग के पक्ष में महिलाएं प्रदर्शन करती हुईं

- थाने के भीतर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे पटवारी, सिंघार आदि नेता.
- थाने पर सारंग के समर्थन में महिलाओं ने किया हंगामा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. केबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ नर्सिंग घोटाले को लेकर मंगलवार की शाम को टीटी नगर थाने पहुंचे कांग्रेसियों को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा.

बड़ी संख्या में पहुंची ये महिलाएं, सारंग पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने के आरोप में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर थाने में हंगामा किया. घटना के समय दोनों पक्ष आमने-सामने थे. दोनों पक्षों ने टीआई से मिलकर अपनी बात रखी.

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कुछ कांग्रेसी केबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पर नर्सिंग घोटाला मामले की एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे. जैसे ही इसकी जानकारी सारंग समर्थक महिलाओं को मिली, तो वे बड़ी संख्या में टीटी नगर थाने पहुंच गई, जिसके बाद महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी पर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने और जनता की सेवा करने के उनके प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाया. सारंग के समर्थन में इन महिलाओं ने नारे लगाए और कांग्रेस के आरोपों को झूठ बताते हुए आलोचना की.

> इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके साथ ही महिलाओं ने हेमंत कटारे और उमंग सिंघार के खिलाफ थाने में आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि विधायक हेमंत कटारे, जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेताओं ने सारंग को निशाना बनाने और जनता की सेवा करने के उनके प्रयासों को बाधित करने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है. उन्होंने दावा किया कि सारंग हमेशा आम लोगों के हिमायती रहे हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने अथक प्रयास किए हैं.

योजना का लाभ जमीन तक पहुंचाए

- सीएम ने शिविर को वीसी के माध्यम से किया संबोधित
- जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी को दी नसीहत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए संकल्प के साथ विकास का क्रम निरंतर जारी है.

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, के ध्येय वाक्य को अंगीकार करते हुए हम सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शासन की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाएं. जन सामान्य की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और तत्परता से किया जाए. उन्होंने कहा कि जाति और निवास प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के आस्था गार्डन में आयोजित जन संवाद शिविर को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिविर में उपस्थित नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी एवं जिला प्रशासन को निराकरण के निर्देश दिए. यादव की ओर से शिविर में उज्जैन आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एक करोड़ 47 लाख ऋण राशि का चेक दिया.

भोपाल डीईओ अंजनी को हटाया

- नेताओं और कर्मचारियों ने जताई थी नाराजगी
- डीईओ का अहिरवार को दिया अतिरिक्त प्रभार

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने के मामले में भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी को लोक शिक्षण आयुक्त ने मंगलवार को आदेश जारी कर हटा दिया है.

त्रिपाठी को डीपीआई में पदस्थ कर दिया गया, वही डीईओ कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक नरेंद्र कुमार अहिरवार को प्रभार दे दिया गया है. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हुई जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में डीईओ त्रिपाठी को हटाने के लिए निंदा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित भी किया गया था. जनप्रतिनिधि भी डीईओ को हटाने की मांग को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग से मिले थे और फिर उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मिलने पहुंचे थे. इस घटनाक्रम के बाद आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने अंजनी कुमार त्रिपाठी को हटाने का आदेश जारी किया.

पेड़ से टकराई बोलेरो बच्ची समेत तीन की मौत

खजुराहो, 16 जुलाई. खजुराहो एयरपोर्ट के पास मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी यूपी 11बीए 9299 अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर डिवाइडर से जा टकराई.

हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं जानकारी के अनुसार, खजुराहो से बमीठा की ओर जाते समय बोलेरो कार एयरपोर्ट रोड के किनारे लगे पेड़ से टकराकर डिवाइड से टकरा गई. बताया गया कि जिसमें महिला पान बाई रजक, 12 वर्षीय बच्ची सृष्टि रजक की मौके पर ही मौत हो गई. युवक आनंद रजक (19) की मौत इलाज के दौरान हो गई.

जातिप्रमाण पत्र न होने पर सालों से कर रहे नौकरी

सरकारी तंत्र की लापरवाही का एक और मामला उजागर

- तय समय पर सत्यापन कर नहीं भेजते अधिकारी
- 47 जवान बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के कर रहे जॉब

कन्हैया लोधी

भोपाल, 16 जुलाई. मप्र में सरकारी तंत्र पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन लापरवाह सिस्टम अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है. इसकी बानगी है कि सरकारी अमला समय पर न तो जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर पा रहा है और न ही चरित्र सत्यापन कर पा रहा है. सिस्टम की इस लापरवाही का खामियाजा

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तक को भुगतना पड़ रहा है. सीआईएसफ जो कि देश के बड़े औद्योगिक कारखानों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी संभालता है, वहां कई ऐसे जवान काम कर रहे हैं, जिनका न तो जाति प्रमाण पत्र अब तक प्रमाणित है और न ही चरित्र की ही कोई गारंटी है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हाल ही में राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें मप्र के सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. सीआईएसएफ के पत्र के बाद सरकार में हड़कंप की स्थिति है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर सरकार के नियमों का हवाला देते हुए आरक्षित वर्ग के ऐसे जवान जो कि सीआईएसएफ में चयनित होकर सेवाएं दे रहे हैं, उनका जाति और चरित्र का सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. पत्र में लिखा है कि विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं, विभागों में आरक्षित पदों पर चयनित व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए भेजे प्रकरण कई वर्षों से लंबित है.

> केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें साफ किया है कि मप्र से आरक्षित वर्ग के 47 ऐसे जवान सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी जाति का अब तक सत्यापन नहीं किया जा सका है. इसी तरह 13 ऐसे जवान भी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका चरित्र सत्यापन अब तक नहीं किया जा सका है. जब तक जाति और चरित्र का सत्यापन राज्य सरकार की ओर से नहीं हो जाता, तब तक ऐसे जवानों की सेवाएं एक तरह से संदिग्ध ही होती है, उनके चरित्र पर संदेह की गुंजाइश बनी रहती है. सीआईएसएफ जैसे संगठन में इस तरह के जवानों का सेवा देना सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है.

जीतू पटवारी का मोबाइल हैक

साइबर डीजी ने जांच उपरांत कार्रवाई का दिया आश्वासन

भोपाल, 16 जुलाई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मोबाइल हेक करने का मामला सामने आया है.

इसकी जानकारी मिलते ही प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को साइबर सेल के डीजी से मुलाकात कर रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की.

कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने साईबर सेल डीजी को बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एप्पल का मोबाइल, जिस पर एप्पल कंपनी से मेल आईडी के माध्यम से हेक किए जाने की जानकारी मिली है. पेगासस स्पाई के माध्यम से पटवारी का मोबाइल हेक किया, जिससे उनके मोबाइल डेटा की जासूसी की जा रही है. पटवारी के मोबाइल का संपूर्ण डेटा चोरी किया जा रहा है.

प्रतिनिधि मंडल ने साईबर सेल से उक्त संबंध में कार्यवाही कर दोषियों को सख्त सजा किये जाने की मांग की है.

> इस अवसर पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया, प्रवक्तागण भूपेन्द्र गुप्ता, शैलेन्द्र पटेल, अभिनव बरोलिया, अमित शर्मा, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षद्वय प्रवीण सक्सेना और अनोखीमान सिंह पटेल सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे.

19 को सीहोर में होगा राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण

भोपाल, 16 जुलाई. एनसीईआरटी के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण कक्षा 3, 6 और 9 की पायलेटिंग कार्य सीहोर में 19 जुलाई को राज्य स्तर से चयनित सेम्पल शालाओं में शाला स्तर पर करेगी. इस कार्य के लिये फील्ड इन्वेस्टीगेटर्स तैयार किए हैं. जिनका दायित्व डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को सौंपा है. राज्य शिक्षा केन्द्र के पीआरओ अमिताभ अनुरागी ने बताया कि सर्वेक्षण के रिजल्ट वास्तविक आ सकें, इसके लिये 30 छात्रों पर एक फील्ड इन्वेस्टीगेटर नियुक्त किया है. सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने कहा हैं.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए समिति गठित

प्रदेश के हर जिले से भेजे जाएंगी तीन उत्कृष्ट अनुशंसाएं

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया गया है.

प्रत्येक जिले से 3 उत्कृष्ट शिक्षकों की अनुशंसाएं 25 जुलाई तक समिति को भेजने के निर्देश डीईओ को दिये गये हैं. उत्कृष्ट अनुशंसाओं के चयन के लिये जिला और राज्य स्तर पर चयन समितियां गठित की गई हैं.

जिला स्तर पर बनी चयन समिति में डीईओ अध्यक्ष, डाइट प्राचार्य और प्रतिष्ठित शिक्षाविद को सदस्य नामांकित किया गया है. शिक्षाविद की नियुक्ति कलेक्टर की अनुशंसा पर होगी. राज्य स्तर पर बनी चयन समिति में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग अध्यक्ष, सदस्यों में भारत सरकार के नामांकित प्रतिनिधि, संचालक एनसीईआरटी शामिल है.

पुरस्कार की ऑनलाइन प्रक्रिया की समय-सारणी तैयार

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की ऑनलाइन प्रक्रिया की समय-सारणी तैयार की है. जिला स्तरीय चयन समिति 3 अनुशंसाएं 25 जुलाई तक राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तरीय चयन समिति नेशनल ज्यूरी नई दिल्ली को 6 उत्कृष्ट शिक्षकों की अनुशंसाएं 4 अगस्त तक भेज सकेंगे. केन्द्र सरकार के शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ठ शिक्षकों के चयन के लिये निर्धारित मापदंड की गाइड लाइन स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित की है. जोकि पोर्टल पर भी प्रदर्शित है.

कम डीए मिलने से नाराजगी

प्रदेश के कर्मचारियों को सता रही चिंता

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता डीए कम मिल रहा है.

जनवरी 2024 से यह डीए 50 प्रतिशत हो जाना था पर अब तक मोहन सरकार में इस पर सुगबुगाहट नहीं है, जिससे कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि ज्यादा दिन होने पर एरियर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार तभी एरियर देती है, जब चुनाव हों और अगले चार साल तक कोई चुनाव नहीं है.

मप्र राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि डीए बढ़ाने की घोषणा इसी माह होनी है, अगर डीए नहीं बढ़ा, तो राज्य के कर्मचारी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई फिर जल्दी नहीं होगी.

तिवारी ने कहा कि जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ डीए और महंगाई राहत न मिलने से राज्य में कार्यरत 7.50 लाख कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनर्स को प्रत्येक महीने 620 से 5640 रुपए का नुकसान हो रहा है. यदि जुलाई से मिलने वाले डीए में भी देरी होती है, तो यह राशि बढ़कर दोगुनी हो जाएगी.

रोड साइड ट्री- प्लांटेशन पॉलिसी बनेगी

- उज्जैन महाकाल मंदिर रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी
- मप्र की परियोजनाओं की गडकरी ने समीक्षा की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक लेकर मध्यप्रदेश में 100 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की.

इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों को शिफ्ट करने की संभावनाओं पर जोर देते हुए मप्र को रोड साइड ट्री-प्लांटेशन पॉलिसी तैयार करने का सुझाव दिया. इसमें राजमार्ग मंत्रालय से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया.

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी. उज्जैन में रोपवे के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी और मप्र सड़क विकास निगम के बीच समझौता हुआ.

18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा

बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के म.प्र. में 18 हजार करोड़ रूपये की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के 4 हजार करोड़ रूपये के 10 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी समीक्षा की. बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाएं, विलंब, भूमि अधिग्रहण एवं वन अनुमतियों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने परियोजनाओं में निर्माण के दौरान होने वाले परिवर्तनों के लिए डीपीआर कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए.

सांची दूध भी दो रुपए महंगा

एमपी में नई दरें आज से लागू होगी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. अमूल के बाद सांची ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए हैं. बुधवार से नई दरें लागू हो जाएगी. सांची ने करीब दो साल बाद केवल दूध के ही रेट बढ़ाए हैं. इस तरह प्रदेश के सभी 6 दुग्ध संघों ने रेट में बढ़ोतरी कर दी है.

सांची कंपनी ने बताया कि 1 लीटर दूध पर 2 रुपए, आधा लीटर दूध पर 1 रुपए बढ़ाया गया है. इंदौर में कल से नए रेट लागू हो चुके हैं, जबकि भोपाल में बुधवार से नए रेट लागू होंगे. भोपाल में पैक्ड दूध में सांची की रोज सवा 3 लाख लीटर तक दूध की खपत है, अमूल की खपत 60 हजार लीटर और सौरभ, श्रीधी, मदर डेयरी की करीब 1 लाख लीटर दूध की खपत शहर और भोपाल के ग्रामीण इलाकों में होती है.

खुले दूध की बिक्री अधिक : भोपाल में पैकेट दूध की तुलना में खुले दूध की बिक्री अधिक होती है. खुले दूध की खपत रोजाना 6 से 8 लाख लीटर तक प्रतिदिन है. इनकी कीमतें भी 60 से 80 रुपए लीटर तक है. फिलहाल सांची ने भी उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर दी है. केवल डीटीएम 160 एमएल टोंड मिल्क एवं परिवार 200 मिमी पैक दूध के रेट नहीं बढ़ाए है.

रेस्क्यू | वन्य प्राणी चिकित्सालय में भर्ती कर किया जा रहा इलाज

घायल शावकों को विशेष ट्रेन से भोपाल लाए

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. बुधनी के मिडघाट पर बाघिन के घायल शावकों को लाने के लिए मंगलवार को रेलवे ने वनविभाग को एक डिब्बे की विशेष ट्रेन दी. अधिकारियों ने दोनों शावकों को ट्रेन से भोपाल लाकर वन्य प्राणी अस्पताल में भर्ती किया.

वही मृत नर बाघ को बुधनी लाकर अंतिम संस्कार कर दिया. इससे पहले सोमवार की दोपहर को बाघिन के आ जाने से रेस्क्यू आपरेशन रोकना पड़ा. इसके बाद शाम से पूरी रात तक बाघिन दोनों घायल शावकों के पास बैठी रही. ज्ञात रहे कि सोमवार को

सुबह करीब 6 बजे सीहोर जिले के बुदनी के मिडघाट रेलवे ट्रैक पर एक बाघ और दो शावक ट्रेन की चपेट में आ गए थे. इस दुर्घटना में बाघ की मृत्यु हो गई. दो शावक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. चल पा नहीं रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद दोनों को मंगलवार को इलाज के लिए वन्य प्राणी चिकित्सालय भोपाल में भर्ती कराने लेकर आए.

सीहोर कलेक्टर के सहयोग से रेलवे ने दी विशेष ट्रेन: सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भोपाल स्थित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क कर की मांग की. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक डिब्बे की विशेष ट्रेन मंगलवार सुबह उपलब्ध कराई, जोकि घटना स्थल मिडघाट तक गई. इस ट्रेन में स्वयं कलेक्टर प्रवीण सिंह भी वनाधिकारियों के साथ गए और दोनों घायल शावकों को ट्रेन से भोपाल लाए.

> **मृत बाघ का बुधनी में किया संस्कार**
>
> मृत बाघ के शव का मंगलवार को पोस्टमॉर्टम कर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉ. गुरुदत्त शर्मा और उनकी टीम ने बुधनी डिपो परिसर में अंतिम संस्कार कराया. बताया जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए वनविभाग ने मुख्यालय से मंजूरी ली थी. सीसीएफ खरे ने बताया कि घायल शावकों को पकड़ने के लिए जाल डाला, मगर बाघिन के सामने आने से रेस्क्यू टीम को लौटना पड़ा. इसके बाद बुधनी के एसडीएम आरएस बघेल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रेन में लाने का निर्णय लिया. इसकी जानकारी सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह को दी. उसके बाद रेस्क्यू किया गया.

प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा : मुख्यमंत्री डॉ .यादव

छिन्दवाड़ा. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिये निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का निर्णय लिया गया है। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सफल बनाने आज छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा स्थित तुलसा होटल में उद्योग संघों व उद्योगपतियों की बैठक में यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचल में सरकार समान रूप से विकास करना चाहती है ।जिसमें कृषि, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आदि की दिशा में एक नये उपलब्धि को हासिल किया जा सके। इसमें कई सारी कठिनाईया आती है लेकिन सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर उनका निराकरण करें। छोटे-बड़े, मझौले सभी उद्यमी सरकार के साथ कदम-कदम से मिलाकर चलेंगे, तो विकास की एक नई धारा प्रवाहित होगी। अभी तक इंदौर में इंडस्ट्री सम्मिट होती थी, लेकिन अब यह प्रदेश के अन्य भागों में भी होगी और वहां के औद्योगिक कठिनाईयों को दूर किया जायेगा। उन्होंने उद्योग संघों व उद्योगपतियों से कहा कि वे निवेश को प्रोत्साहित करें। इसके लिये उन्हें औद्योगिक नीति अनुसार सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। 5 साल में प्रदेश की जीडीपी को डबल करने के लक्ष्य रखते हुये मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि निवेश को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो बेहतर हो सकता है उस दिशा में निवेश में अनुकूलता लाना है। औद्योगिक विकास के लिये प्रदेश में पर्याप्त लेंड बैंक है। बैठक में उन्होंने औद्योगिक निवेश में रोजगार मूलक गतिविधि और स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण पर जोर दिया गया । उन्होंने उद्योगों के स्थापना में सब्सिडी का जिक्र करते हुये बॉयर- सेलर के बीच की कठिनाईयों को दूर कर उद्योग और व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। इन सब बातों में उन्होंने स्थानीयता को विशेष महत्व देते हुये कहा कि स्थानीय स्तर पर कच्चा माल को उपयोगी बनाये और रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़ायें। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने सभी जिला कलेक्टरों से उद्योग और व्यापार संघों की कठिनाईयों को समझने तथा उसे दूर करने और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिये कहा, ताकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और उनकी बेहतरी के लिये सुझाव भी हो। उन्होंने दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के सफल प्रयास पर जोर दिया। इसके साथ ही कहा कि जिला प्रशासन संभावित उद्योगों की जानकारी बतायें जिससे पूरे संभाग में उद्योगों की संभावनाओं की दिशा में कारगर कार्य किया जा सके।